भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5263

मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में उद्योग विभाग

5263. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में उद्योग विभाग की वर्तमान संरचना और कार्य क्या हैं;

(ख) विभाग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ, योजनाएं और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र में विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र में विभाग की पहल के माध्यम से कितने रोजगार सृजित हुए हैं और कितने लाभार्थी प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा द्वीपों में उद्यमशीलता, स्थानीय उद्योगों और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा सूचित किया गया है कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में उद्योग विभाग का प्रमुख कार्य, लघु और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू करना तथा नारियल आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। यह विभाग प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी सुगम बनाता है और एमएसएमई इकाइयों की स्थापना में स्थानीय उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह विभाग लक्षद्वीप में पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा स्कीम जैसी स्कीमों को लागू करता है।

(ख): इस संघ राज्य क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अगत्ती, अमिनी, एंड्रोट, कदमाथ और कावारत्ती में स्थित कॉयर उत्पादन केंद्र (05); (ii) अगत्ती, अमिनी, एंड्रोट, कदमाथ, कल्पेनी, कावारत्ती और किल्टन में स्थित कॉयर

फाइबर कारखाने (07) (iii) कावारत्ती में स्थित हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र (01); और (iv) कल्पेनी में स्थित होजरी फैक्ट्री (01)।

25% पूंजी निवेश सब्सिडी स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप के उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित एकमात्र राज्य स्कीम है। इस स्कीम के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना करने वाले पात्र स्थानीय उद्यमियों को पूंजी निवेश का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है जिससे इस द्वीप समूह में औद्योगिक विकास, स्वरोजगार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है।

(ग): पिछले तीन वर्ष के दौरान उद्योग विभाग द्वारा आबंटित और उपयोग की गई कुल निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**निधि आबंटन (लाख रुपए में)**	**उपयोग की गई निधि (लाख रुपए में)**
2023-24	20.00	20.00
2024-25	20.00	20.00
2025-26	20.00	20.00

(घ): वर्ष 1987 से लागू 25% पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम, हर वर्ष लगभग 10 एमएसएमई को सहायता प्रदान करती है। अब तक कुल 198 एमएसएमई इकाईयों को 1,91,89,954 रुपए की कुल सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है। इस पहल ने लक्षद्वीप में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, लघु उद्योगों को सुदृढ़ करने और सतत आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीमें भी प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, 441 लाभार्थियों (पंजीकृत लाभार्थियों का 66%) को मूलभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 42 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 19 लाभार्थियों को 15,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता संवितरित की गई है।

इसके अलावा, यह विभाग हस्तशिल्प प्रशिक्षण, कॉयर आधारित मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण, महिला कॉयर योजना और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त होता है।

(ङ): सरकार ने लक्षद्वीप में उद्यमिता और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें एमएसएमई इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रावधान,

हस्तशिल्प और कॉयर आधारित क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन; और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) का आयोजन शामिल हैं।

लक्षद्वीप में नारियल की प्रचुर उपलब्धता है, जो नारियल और मछली आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त प्राकृतिक लाभ प्रदान करती है। इस संदर्भ में, इस विभाग ने मूल्य संवर्धन बढ़ाने, आय सृजन में सुधार करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नारियल और मछली आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों, विशेष रूप से नारियल फ्लेक्स और वर्जिन नारियल तेल पर फोकस करते हुए एक औद्योगिक क्लस्टर के विकास और स्थापना की पहल की है।

उद्योग विभाग ने कावारत्ती और अगत्ती द्वीपों में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के लिए दो फेस्ट आयोजित करके बाजार संपर्क पहल की भी शुरूआत की है, जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री हुई है। उद्योग विभाग को लक्षद्वीप में रैम्प (रेजिंग एंड एक्सीलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) को लागू करने संबंधी अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।

****